भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 3757

सोमवार, 24 मार्च, 2025/03 चैत्र, 1947 (शक)

वैश्विक क्षमता केंद्रों में रोजगार वृद्धि

3757. डॉ. भोला सिंह:
श्री पी. सी. मोहन:
श्रीमती संध्या राय:
श्री कोटा श्रीनिवास पूजारी:
कैप्टन बृजेश चौटा:
श्री धर्मबीर सिंह:
श्रीमती स्मिता उदय वाघ:
डॉ. हेमंत विष्णु सवरा:
श्री बलभद्र माझी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे विशिष्ट नीतिगत उपायों का ब्यौरा क्या है कि देश में वैश्विक क्षमता केन्द्रों (जीसीसी) का विकास भारतीय पेशेवरों के लिए सुरक्षित और सतत रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो जाए;

(ख) क्या जीसीसी क्षेत्र के विस्तार के लिए कुशल कार्यबल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमता (एआई), साइबर सुरक्षा और ब्लॉकचेन के क्षेत्र में उद्योग-अकादमिक भागीदारियों को सुकर बनाने के लिए सरकार द्वारा कोई पहल की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बेंगलुरू जैसे प्रौद्योगिकी कंपनियों वाले शहर में वैश्विक क्षमता केंद्र स्थापित करने की सरकार की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के साथ भारत की भागीदारी में विनियामक ढांचे का निर्माण शामिल होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जीसीसी का तीव्र विस्तार वैश्विक श्रम मानकों के अनुरूप हो; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा अनेक पहलें की गई हैं जिन्होंने भारत में वैश्रिवक क्षमता केन्द्रों (जीसीसी) के विकास के लिए एक प्रवर्तक के रूप में कार्य किया है। नैसकॉम-जिनोव रिपोर्ट के अनुसार, भारत में

1,700 से अधिक जीसीसी हैं, जो 64.6 बिलियन अमरीकी डालर का राजस्व अर्जित करते हैं और सीधे तौर पर 1.9 मिलियन से अधिक लोगों को रोज़गार देते हैं।

सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), साइबर सुरक्षा और ब्लॉकचेन के लिए विभिन्न पहल/उपाय किए हैं।

माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 मार्च, 2024 को भारत के विकास लक्ष्यों के अनुरूप एक मजबूत और समावेशी एआई पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने की रणनीतिक पहल के रूप में इंडियाएआई मिशन को मंजूरी दी। इस मिशन का उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देकर, घरेलू क्षमताओं को बढ़ाकर और देश की तकनीकी संप्रभुता सुनिश्चित करके भारत को कृत्रिम बुद्धिमत्ता में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है।

सरकार ने देश में साइबर सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने और देश में साइबर सुरक्षा मामलों से निपटने के लिए कई कानूनी, तकनीकी और प्रशासनिक नीतिगत उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ (i) राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक (एनसीएससी) (ii) भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सीईआरटी-इन) (iii) राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (एनसीसीसी) (iv) साइबर स्वच्छता केंद्र (सीएसके) (v) गृह मंत्रालय द्वारा स्थापित भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) (vi) सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 की धारा 70ए के प्रावधानों के तहत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (एनसीआईआईपीसी) शामिल हैं।

इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विभिन्न अनुमति प्राप्त ब्लॉकचेन आधारित अनुप्रयोगों को सक्षम करने के लिए भौगोलिक रूप से वितरित बुनियादी ढांचे के साथ ब्लॉकचेन-ऐज़-ए-सर्विस की पेशकश करने के लिए विश्वस्य- ब्लॉकचैन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया। इस पहल के तहत, ब्लॉकचैन आधारित अनुप्रयोगों के डिपलॉयमेंट तथा एंड-टू-एंड विकास के लिए आवश्यक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बुनियादी ढांचे के साथ एक पूर्ण ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक विकसित किया गया है।

भारत सरकार का विजन भारत को वैश्विक कौशल केंद्र तथा पूरे विश्व में विभिन्न क्षेत्रों के लिए एक विश्वसनीय और उच्च कुशल कार्यबल के रूप में निर्मित करना है।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा संबंधित क्षेत्रों में उद्योग जगत के अग्रणी लोगों के नेतृत्व में 36 सेक्टर स्किल काउंसिल (एसएससी) की स्थापना की गई है जिनका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों की कौशल विकास आवश्यकताओं की पहचान करना तथा घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के उद्योगों की कुशल जनशक्ति की आवश्यकता को पूरा

करना है। कौशल विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत पाठ्यक्रमों को सेक्टर स्किल काउंसिलों (एससीसी) से प्राप्त इनपुट के साथ आवधिक अंतरालों पर अद्यतन किया जाता है ताकि विभिन्न क्षेत्रों में चिन्हित कौशल संबंधी कमियों को दूर किया जा सके।

तदनुसार, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 4.0 के तहत, सरकार ने कोडिंग, एआई, रोबोटिक्स, मेक्ट्रोनिक्स, आईओटी, 3 डी प्रिंटिंग, ड्रोन, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे नए युग और फ्यूचर स्किल पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) भी ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेक्ट्रोनिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सुरक्षा, सेमीकंडक्टर आदि जैसे 29 नए युग/ फ्यूचर स्किल पाठ्यक्रमों में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।

इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नैसकॉम ने फ्यूचरस्किल्स प्राइम प्रोग्राम के माध्यम से पेशेवरों की अप स्किलिंग में सहयोग किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 10 नई/उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग/3डी प्रिंटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, सोशल एंड मोबाइल, साइबर सिक्योरिटी, ऑगमेंटेड/वर्चुअल रियलिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ब्लॉकचैन में आईटी पेशेवरों का रि-स्किलिंग / अप-स्किलिंग करना है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के संस्थापक सदस्य के रूप में भारत सद्भावनापूर्ण रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों का सम्मान करता है और उन्हें बढ़ावा देता है। देश ने प्रमुख आईएलओ सम्मेलनों की पुष्टि की है जिनमें जबरन श्रम, बाल श्रम और रोजगार में भेदभाव से संबंधित विषय शामिल हैं।

*****